संख्या-140/2024/I/794910/2024/71-1099(099)/3/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 13 नवम्बर, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-1) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में 50 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत भवन निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2024-25/45, दिनांक 04.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अंतर्गत मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज प्रयागराज में 50 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत भवन निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित आगणन रू0 4997.46 लाख की प्रति उपलब्ध कराते हुए उक्त आगणन का परीक्षण पी0एफ0ए0डी0 से कराते हुए कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-160/2023/I/457052/2023/71-1099(099)/3/2021, दिनांक 27.12.2023 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अंतर्गत मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज प्रयागराज में 50 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत भवन निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 4700.05 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 1175.00 लाख की धनराशि (केन्द्रांश) अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-1) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में 50 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत **भवन निर्माण कार्य** हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 4862.35 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त शासनादेश दिनांक 27.12.2023 द्वारा निर्गत धनराशि रू0 1175.00 लाख (केन्द्रांश) को परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में **समायोजित** किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. प्रयोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
2. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।
3. वित्त विभाग के शासनादेश सं0- 10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22.03.2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायेाजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरांत इसी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरांत ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रकिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष स्वीकृत लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रयोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
4. प्रायोजना प्रस्ताव में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो।
5. प्रायोजना निर्माण में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन0एम0सी0) के मानकों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित फर्नीचर एवं स्पिलिट ए0सी0 को अनुमन्य नहीं किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना निर्माण के उपरान्त इसका क्रय एवं स्थापना पृथक से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए किया जाय।
7. प्रयोजना प्रस्ताव में लिफ्ट ट्रान्सफार्मर आदि की लागत कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर प्रस्तावित की गयी । प्रभाग द्वारा इस इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्ण कार्यदायी संस्था इस हेतु प्रतिस्पर्धा के अधार पर लागत दरों प्राप्त करें। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार सुनिश्चित कराया जाय।
8. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
9. प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 36.50 लाख सिविल लागत के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विस्तृत लागत विवरण निर्माण से पूर्व प्राप्त कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य किया जाय।

10. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।

11. प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।

12. प्रयोजना प्रस्ताव आगणन/में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एंव अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

13. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

14. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

16. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

18. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को बैक खाते/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

19. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
4. अन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम , लि0 लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।